

“बीआरआई (BRI) को इटली का प्रस्तावित समर्थन यूरोपीय संघ के भीतर की दुविधाओं को उजागर करता है।”

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समर्थन देने की इटली की योजना, जो G7 सदस्यों द्वारा इस तरह का पहला कदम है, चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगी। बदले में, यह यूरोपीय संघ और अमेरिका के सामने आने वाली कठिनाईयों को उजागर करती है, ताकि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया तैयार की जा सके।

2013 में बी.आर.आई. की स्थापना के बाद, इसने एक आधुनिक सिल्क रोड के साथ लगभग 65 देशों को जोड़ने की परिकल्पना की थी, जो चीन को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने और रेनमिनबी का वैश्विक मुद्रा में उन्नयन करने से भी संबंधित है।

आज, यह 80 से अधिक देशों में विस्तारित हो चुका है, जिसमें ज्यादातर कम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि बीजिंग अपनी मेड इन चाइना 2025 औद्योगिक नीति को बढ़ावा देना चाहता है। बीआरआई का प्रलोभन काफी हद तक सौदों की अनौपचारिक प्रकृति के लिए जिम्मेदार है, जहाँ बीजिंग आकर्षक ऋण शर्तों और राजनीतिक शृंखला के साझेदार, देशों के साथ बातचीत करता है।

उसकी अपारदर्शी प्रकृति की आलोचना भी हुई है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें देशों को एक ऋण जाल में धकेल दिया जाता है। बीजिंग के अन्य उपक्रम अर्थात् एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ बीआरआई आगे बढ़ गया है। कई मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश, यूरोपीय संघ के सदस्य '6+1' समूह का हिस्सा हैं, जिसमें चीन भी शामिल है, जो बुनियादी ढांचा उपक्रमों में सहयोग कर रहा है।

हालांकि, यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य, इटली बीआरआई में भाग लेने वाली पहली प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था होगी। रोम का सत्तारूढ़ यूरोसेप्टिक और स्थापना विरोधी गठबंधन इस पर हस्ताक्षर करने में उत्साही रहा है। इस समय ऐसा लगता है कि सरकार को यूरोपीय संघ के कठोर राजकोषीय मानदंडों के साथ अपने विकास लक्ष्यों को संतुलित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।



यह तनाव ब्रशेल्स के साथ हाल ही में हुई बातचीत में भी सामने आया है, जिसके कारण एक संशोधित इतालवी बजट आया। यूरोपीय संघ में चीनी बहिर्वाह में हाल ही में हुई कटौती को देखते हुए इटली इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने बीआरआई समर्थन को दर्शा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस महीने की यात्रा के दौरान रोम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद की जा रही है।

ब्लॉक के रणनीतिक आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए चीनी कंपनियों के विलय और अधिग्रहण का मुकाबला करने के लिए इटली की चाल यूरोपीय राजधानियों, विशेष रूप से पेरिस और बर्लिन में बढ़ती चिंता का एक क्षण है। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों को लागू किया, जो शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाता है।

इसके साथ ही बीजिंग पर दंडात्मक आयात शुल्क लगाया, जिसे घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया गया है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद से चीन के अभूतपूर्व आर्थिक विस्तार ने वैश्विक परिदृश्य को लगभग बदल दिया है। लेकिन चीनी व्यवसायों को अवरुद्ध करने का प्रयास अदूरदर्शी साबित हो सकता है।

इसके बजाय, पश्चिमी लोकतंत्रों को संरक्षणवाद से बचने और नियमों पर आधारित खुली और मुक्त वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अपने वादों को जीने का प्रयास करना चाहिए।

GS World टीम्स

वन बेल्ट, वन रोड

परिचय

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर, 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- प्रस्तावित 'वन बेल्ट, वन रोड' 1400 अरब डॉलर की परियोजना है। ओबीओआर को 35 वर्ष में पूरा किये जाने की लक्ष्य है, जब 2049 में चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन- मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत -चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।
- यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है- (i) चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग। (ii) चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्यसागर से जोड़ने वाला मार्ग। (iii) चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।
- 'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिन्द महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिये किया गया है।

इन गलियारों से जाल बिछाएगा चीन

1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
2. न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज

3. चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा
4. चीन-मंगोलिया-रूस आर्थिक गलियारा
5. बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा
6. चीन-इंडोचाइना-प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा

चीन के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों?

- विशेषज्ञों का मानना है कि 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल चीन की आर्थिक कूटनीति का खाका है।
- विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन स्वयं को अकेला महसूस करता है क्योंकि वह जी-7 में शामिल नहीं है और केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है।
- उनका मानना है कि अपने आर्थिक विस्तार को जारी रखने के लिये चीन को एक नीति की आवश्यकता थी और 'वन बेल्ट वन रोड' पहल ने उसकी इस मंशा को बखूबी पूरा किया है।

भारत के लिए लाभ

- प्रतिस्पर्धी नेटवर्क स्थापित करने के लिये आज भारत में संसाधनों की कमी है। इसलिये वह OBOR के उन घटकों में भाग लेने के लिये उपयुक्त हो सकता है जो प्रमुख बाजारों और संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारतीय कनेक्टिविटी में सुधार ला सकते हैं।
- इसमें 60 देशों के साथ-साथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), ब्रिक्स के नव विकास बैंक, सिल्क रोड फंड, सीआईसी के समर्थन वाले कोष और संभवतः एससीओ विकास बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जुड़ रहे हैं और साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन हासिल है।
- यदि भारत को 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है तो एशियन मार्केट को बिना एकीकृत किये यह संभव नहीं हो सकता है इसलिये इस परियोजना में शामिल होकर एशियाई बाजारों के एकीकरण में हिस्सेदार बनना चाहिये और उसका लाभ भी उठाना चाहिये।

भारत पर प्रभाव

- भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन का वन बेल्ट,

वन रोड का सपना साकार हो गया तो चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है।

- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी ओबीओआर का ही हिस्सा है।
- भारत, चीन-पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। भारत की नजर में यह कॉरिडोर उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।
- ओबीओआर के माध्यम से चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को नई दिशा देना चाहता है जो इसने दक्षिण एशिया में करना भी शुरू कर दिया है, भारत पर इसका सीधा तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा। चीन की इस पहल में भू-राजनीतिक उद्देश्य निहित हैं।

सिल्क रूट क्या है ?

- सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ा। 5वीं से

8वीं सदी तक चीनी, अरबी, तुर्की, भारतीय, पारसी, सोमालियाई, रोमन, सीरिया और अरमेनियाई आदि व्यापारियों ने इस सिल्क रूट का काफी इस्तेमाल किया।

- ज्ञातव्य है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने-अपने उत्पादों जैसे घोड़ों इत्यादि का व्यापार भी करते थे।
- लद्दाख के एक बड़े इलाके पर चीन का कब्जा है, उसके पश्चिम में पाकिस्तान ने अपने कब्जे का एक बड़ा हिस्सा 1962 की भारत-चीन लड़ाई के बाद चीन को सुपुर्द कर दिया है। सकाराकोरम हाइवे कश्मीर में चीन का पहला trans-border infrastructure project है जो साठ के दशक का है।
- तब से ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन का दखल बढ़ता गया है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ जुड़ने से कश्मीर विवाद में चीन की भूमिका और बढ़ गई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक इटली, बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव में भाग लेने वाली यूरोप की पहली प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था होगी।
2. G-7 के सदस्य देशों में इटली के साथ-साथ चीन भी शामिल है।
3. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेण्ट बैंक का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है।
4. BRI के तहत चीन अफगानिस्तान में चाबहार बन्दरगाह का निर्माण कर रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 3
- (c) 1, 2 और 4
- (d) उपरोक्त सभी

1. Consider the following statements-

1. Italy, one among the founder members of European Union, will be the first main developed economy to participate in Belt and Road Initiative.
2. China along with Italy, is also included in member countries of G-7.
3. The headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank is in Zakarta.
4. Under the BRI, China in constructing Chabahar Port in Afghanistan.

Which of the following statements is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) 1 and 2
- (c) 1, 2 and 4
- (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: चीन की महत्वाकांक्षी योजना BRI एशिया से आरम्भ होते हुए यूरोप तक पहुँचती है। इस कथन के सन्दर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

Q. China's ambitious project BRI starts from Asia and reaches Europe. In the context of this statement, discuss the impacts of it on Global Economy.

(250Words)

नोट : 8 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।